



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-10092024-257049
CG-WB-E-10092024-257049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 711]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(मानव संसाधन प्रबंधन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै)

अधिसूचना

चेन्नै, 10 सितम्बर, 2024

सं. एचआरएमडी/पेंशन/001/2024.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, आइओबी बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् -

- (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 2 के खंड (एस) के उपखंड (डी) में, निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"बशर्ते कि 1 नवंबर, 2012 से लागू विशेष भत्ता का हिस्सा नहीं बनेगा।

बशर्ते कि वे कर्मचारी जो 1 नवंबर 2017 को बैंक की सेवाओं में थे और जिनकी रुकी हुई वेतन वृद्धि को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार फिर से समायोजित किया गया है, वह इस तरह के संशोधित के लिए कल्पित रूप से पेंशन के प्रयोजनों के लिए 1 नवंबर 2017 से स्थिर वेतन वृद्धि/यों हेतु पात्र होंगे, जो इस तरह के पुनः समायोजन के कारण उपचित मौद्रिक लाभ केवल 1 नवंबर 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

3. उक्त विनियम के नियम 22 के, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थातः -

"बशर्ते कि किसी कर्मचारी को, जो वेतनमान के आधार पर बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक रूप से कार्यरत है या स्थायी आधार पर अंशकालिक रूप से कार्यरत है, को हटाने से उसकी पूरी पिछली सेवाएँ जब्त नहीं होंगी और वह पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे"

4. उक्त विनियम के विनियम 36 में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थातः-

"(जी) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा, किसी कर्मचारी के संबंध में जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ है रुपये प्रति माह तीन हजार नौ सौ पचासी रुपये एवं जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ है $\frac{1}{3}$ स्केल वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति माह, $\frac{1}{2}$ स्केल वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में दो हजार रुपये प्रति माह और $\frac{3}{4}$ स्केल वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रति माह निर्धारित है।

5. उक्त विनियमों के विनियम 40 में,

(ए) उप-विनियम (1),-

(i) खंड (बी) में, पहला परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

"बशर्ते बेटा/बेटी (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन तब बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी जब पात्र बेटा/बेटी सरकारी/निजी क्षेत्र/स्वरोजगार में रोजगार से रुपये 12,000 प्रति माह से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर दें।"

(ii) खंड (सी) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

"(सी) माता-पिता के मामले में पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी यदि सरकारी/ निजी क्षेत्र/ स्व-रोजगार में रोजगार से माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय रुपये 12,000 प्रति माह से अधिक हो।"

(बी) उप-विनियम (4) में, -

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित पढ़े जाएंगे, अर्थातः -

"(vii) छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, दोनों अधिकारी और कर्मकार के संबंध में है, जो नवंबर 2017 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मृत हुए हो।"

बशर्ते कि 01 अप्रैल 2021 से इस विनियम के उप खंड (i) से (vii) के प्रावधानों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के अनुसार देय होगी।

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित पढ़े जाएंगे, अर्थातः -

"(vii) दोनों अधिकारियों और कर्मकारों के संबंध में छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रति माह केवल उन कर्मचारियों जो 01 नवंबर, 2017 के दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मृत हो गए :

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से, उप खंड (i) से (vii) का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) या उप-विनियम 39 के उप-विनियम (1) जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (VI) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

“(VII) प्रति माह तेरह हजार दो सौ अस्सी रुपये मात्र अर्जित करने वाले, कर्मचारियों, अधिकारी और कर्मकार दोनों के संबंध में, जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद हुई है :”

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2021 से उप-खण्ड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियमन 39 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट II में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

4. 01 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, औद्योगिक कर्मकारों के लिए महंगाई राहत अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960=100 के श्रृंखला में त्रैमासिक औसत में 2288 अंकों से अधिक के प्रत्येक 4 अंकों में से प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि 1 मई 2005 को और उसके बाद से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, इस खंड के अनुसार महंगाई राहत देय होगी :

बशर्ते कि आगे 1 नवंबर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, औद्योगिक कर्मकारों के लिए महंगाई राहत अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960=100 के श्रृंखला में त्रैमासिक औसत में 2836 अंक से अधिक के प्रत्येक 4 अंक पर प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि यह भी 1 नवंबर 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, औद्योगिक कर्मकारों के लिए महंगाई राहत अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960=100 के श्रृंखला में त्रैमासिक औसत में 4440 अंक से अधिक के प्रत्येक 4 अंक पर प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि यह भी 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई राहत अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960=100 के श्रृंखला में त्रैमासिक औसत में 6352 अंक से अधिक के प्रत्येक 4 अंक पर प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-III में, खंड (एफ) के बाद निम्नलिखित खंडों को जोड़ा जाएगा, अर्थात: -

(जी) 1 नवंबर, 2017 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी एवं कर्मकार दोनों) के मामले में :

प्रतिमाह वेतन	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 15,880 तक	‘वेतन’ का 30% मूल पारिवारिक पेंशन होगा और भत्ते का 30% जिसे भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिना जाता है किंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता है, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी:

	बशर्ते कि मूल एवं अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग रु. 3,985 प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु. 15,881 से रु. 31,760 तक	‘वेतन’ का 20% मूल पारिवारिक पेंशन होगा और भत्ते का 20% जिसे भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिना जाता है किंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता है, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल एवं अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग रु. 4,900 प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु. 31,760 से ऊपर	‘वेतन’ का 15% मूल पारिवारिक पेंशन होगा और भत्ते का 15% जिसे भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिना जाता है किंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता है, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल एवं अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग रु. 6,365 प्रतिमाह से कम एवं रु. 13,280 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(एच) 1 अप्रैल 2021 से खंड (ए) से (जी) का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उक्त खंड में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (दोनों अधिकारी और कर्मकार) के संबंध में, ‘वेतन’ का 30 प्रतिशत होगा मूल पारिवारिक पेंशन और भत्ते का 30%, जिसे भविष्य निधि में योगदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी।

विवरणात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों और शीर्ष कर्मचारी यूनियन एवं अधिकारी संघ द्वारा दिए गए विशिष्ट जनादेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौते और भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। अतः इस तरह के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दि.कु. बारिक, महा प्रबंधक (म.सं.प्र.वि)

[विज्ञापन-III/4/असा./481/2024-25]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या पीएडी /179/2097, दिनांक 29 सितम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम बार अधिसूचना संख्या एचआरएमडी/पीईएन/001/2023, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 द्वारा संशोधित किए गए हैं।

INDIAN OVERSEAS BANK

(Human Resources Management Department)

(HEAD OFFICE: CHENNAI)

NOTIFICATION

Chennai, the 10th September, 2024

No. HRMD/PEN/001/2024.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of subsection (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Overseas Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Overseas Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos Shall be inserted, namely: --

"Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:

Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later."

3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the removal of an employee who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages. shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits."

4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017."

5, In regulation 40 of the said regulations, ---

(a) in sub-regulation (1),---

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:--

"Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:--

"(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self-employment, exceeds rupees twelve thousand per month;"

(b) in sub-regulation (4),---

(i) in clause (a), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:--

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clauses (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.";

(ii) in clause (b), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:--

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.";

(iii) in clause (c), after the sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely:--

"(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39."

6. In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4), the following shall be substituted, namely: -

"(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for

every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007 dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension.”.

7. In Appendix III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:--

"(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of Pay Per Month	Amount of monthly family Pension
(1)	(2)
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 20 per cent. of allowance which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowance which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent. of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of

specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

D. K. BARIK , General Manager – HRMD

[ADVT.-III/4/Exty./481/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* notification number PAD/ 179/2097, dated the 29th September, 1995 and lastly amended, *vide* notification number HRMD/PEN/001/2023, dated the 27th October, 2023.